जय प्रकाश पांडे

कॅरिअर बनाने की दिशा में बहु-विषयक पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 परिवर्तन के ऐसे माध्यम की भूमिका निभाएगी जिससे 'नया भारत' के भविष्य की सुदृढ़ नींव रखी जाएगी। इस नीति के तहत 'स्कूली बस्ते का बोझ' बढ़ाने की बजाय अनुभवजन्य शिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा और 'रोज़गार खोजने वाले' नहीं बल्कि 'रोज़गार उपलब्ध' कराने वाले युवाओं का विकास किया जाएगा जो 21वीं सदी में भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के सर्वथा अनुरूप होगा। - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

तनुष्का दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर रही है। उसने मुख्य विषय अर्थशास्त्र के साथ 'वैश्वीकरण की राजनीति' को सामान्य वैकल्पिक विषय चुना है और डिजिटल सशक्तीकरण को एक मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम, रचनात्मक लेखन को कौशल विकास पाठ्यक्रम तथा संस्कृत पाठ्यक्रम को योग्यतावर्द्धक विषय के रूप में अपनाया है। तनुष्का शैक्षिक विषयों को पढ़ने के साथ ही अपना शौक और अपनी स्वाभाविक कला में रुचि बनाए रखने की दृष्टि से कॉलेज की डांस सोसाइटी में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। इस प्रकार उसने विविध और व्यापक शिक्षा-यात्रा का मार्ग अपनाया है। इस लचीली और बहु-विषयक अध्ययन योजना को कार्यरूप देना उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रकार की पहल से विद्यार्थियों को अपनी पूरी मानवीय क्षमता से भविष्य के लिए अपनी पसन्द और संतुष्टि के अनुरूप कॅरिअर चुनकर आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 वास्तव में दूरदर्शितापूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें संज्ञानात्मक शिक्षण के विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों में नया जानने-करने की जिज्ञासा और विवेचनात्मक विचारों का संचार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है जो जांच-परख, चर्चा और विश्लेषण पर आधारित हो और प्राथमिक-पूर्व स्तर से उच्च शिक्षा स्तर तक के सभी विद्यार्थियों में सीखने की उत्सुक्ता, जिज्ञासा और इच्छा जागृत करे। इस नीति में शिक्षा प्रणाली में संगठनात्मक बदलाव लाने की योजना तैयार की गई है जिससे शिक्षण व्यवस्था में 'क्या सोचें' की जगह 'कैसे सोचें' सिखाने पर विशेष बल दिया जा सके और शिक्षण की लचीली, बहु-विषयक और समग्र सोच विकसित हो सके।

पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, समानता और न्याय पर आधारित समाज का विकास करने, राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने और 21वीं शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा ही मूल आधार है तथा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर बहु-विषयक शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में पढ़ने-पढ़ाने की बहु-विषयक पहल अपनाने पर भरपूर ज़ोर दिया गया है।

लेखक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अपर सचिव और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पूर्व-निदेशक हैं।
ईमेल : jppandeyirps.upsc@gov.in

समग्र शिक्षण

शिक्षा की बहु-विषयक व्यवस्था में विषयों के समन्वयन और अधिक समग्र तथा सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम अपनाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह सीखने-सिखाने का ऐसा तरीका है जिसमें अध्ययन के विभिन्न विषयों या क्षेत्रों की शिक्षण सामग्री और शिक्षण के तौर-तरीकों को समाहित किया जाता है। बहु-विषयक शिक्षा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किसी एक ही विषय या किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान देने तक सीमित रखने की बजाय उन्हें विभिन्न एवं विविध विषयों का ज्ञान उपलब्ध कराने के अनेकानेक तरीके अपनाने पर ज़ोर दिया जाता है। इसमें विषयों का समन्वयन, परस्पर जुड़ी हुई शिक्षण व्यवस्था और सहयोग पर आधारित ज्ञान शामिल रहता है। शिक्षा में यह बहु-विषयक व्यवस्था विषय आधारित रूढ़िवादी व्यवस्था से छुटकारा दिला सकती है और विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षण प्राप्त करने और अपने भविष्य के लक्ष्य हासिल करने में सहायक बन सकती है। इस व्यवस्था से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के इस नए दौर की मूलभूत आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में स्वामी विवेकानन्द की 'मानव निर्माण शिक्षा', श्री अरविन्दो की 'समेकित शिक्षा' और महात्मा गांधी की 'बुनियादी शिक्षा' का मूल सार स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसमें संचार, अनुकूलन, समन्वयन, सहयोग, मिलकर कार्य करने, नेतृत्व, जवाबदेही, समानुभूति, करुणा, लचीलापन इत्यादि जैसे जीवन कौशल को 'सॉफ्ट स्किल' तथा ज्ञान के क्षेत्र में महारत और दक्षता प्राप्त करने को 'हार्ड स्किल' माना जाता है। इन दोनों प्रकार के कौशलों के संयोजन से ज्ञान तथा अन्तर वैयक्तिक विशेषताओं के बीच प्रभावी संतुलन की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार इस व्यवस्था से विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल की शैक्षिक विशेषज्ञता विकसित करने की धारणा है जिससे उन्हें भविष्य बनाने की दिशा में काफी मदद मिलेगी। प्राचीन भारत में भी शिक्षा प्रणाली का यही आधार था। समय की कसौटी पर परखी-जांची हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति के समग्र विकास पर ही ज़ोर दिया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परम्पराओं और व्यवहार का ऐसा स्रोत मानी जाती थी जो विशेषज्ञता के साथ ही मानवीय गुणों के विकास को प्रेरित करती है। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक और पेशेवर कौशल की ट्रेनिंग देने के साथ ही ललित कलाओं, चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान, गणित, नक्षत्र विज्ञान, विधि (कानून), राजनीति और युद्धकला का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। विनम्रता, सत्यवादिता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन के सभी अन्य पहलुओं पर भी ज़ोर दिया जाता था। बहु-विषयक शिक्षण केवल शैक्षिक व्यवस्था न होकर विश्व को समझने का प्रभावी माध्यम था।

इस प्रकार बहु-विषयक शिक्षा से भारतीय शिक्षण संस्थानों को ऐसे महत्वपूर्ण विचारक तैयार करने में मदद मिलेगी जो अपनी शिक्षा के व्यापक ज्ञान का प्रयोग करके नए युग की समस्याओं का हल खोजने के एकदम नए उपाय सोच सकते हों। इस व्यवस्था में मूल्य-आधारित शिक्षा और वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) पर विशेष बल दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों को वैश्विक दृष्टि से जागरूक बनाया जा सके, रोज़गार सृजन बढ़े और स्वतंत्र रूप से सोच सकने वाले नैतिक नागरिक बनकर तैयार हों। इस प्रकार की व्यवस्था होने से शिक्षण के परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे और नवाचारों का विकास होगा और विभिन्न विषयों की ज्यादा गहन जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। अनुभवजन्य शिक्षण और कलाओं तथा खेलकूद के समन्वयन से विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा और वे अधिक प्रेरित और उत्साहित होकर आगे बढ़ेंगे। परियोजनाओं, परीक्षणों, और चर्चा-गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच विकसित होगी, वे अधिक प्रभावी ढंग से आपसी सहयोग कर पाएंगे तथा विभिन्न विषयों के बीच के संबंधों को और अच्छे से समझ सकेंगे। इससे शिक्षण के प्रति लगाव बढ़ेगा जो पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान से कहीं ज्यादा अहम है और वर्तमान गतिशील और परस्पर जुड़े विश्व में अपने सफल भविष्य की ओर बढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है।

कॅरिअर और रोज़गार सृजन

भारत में कॅरिअर की परंपरागत धारणा के तहत स्थायी कार्य अथवा नौकरी पा लेना और किसी व्यवसाय के लिए उपयुक्त या फिट हो जाना ही महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। परन्तु बदलते विश्व परिवेश और 21वीं शताब्दी की नई उभरती मांगों को देखते हुए पहले से बिल्कुल अलग कौशल और प्राथमिकताएं जरूरी हो गई हैं। नौकरियों के लिए अब अलग तरह के कौशल और महारत की जरूरत होने लगी है, अतः नौकरियों के प्रति रवैया भी उसी प्रकार बदलना चाहिए। विद्यार्थियों को नौकरियों के उपयुक्त बनाने और उन्हें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को समझने योग्य बनाने के वास्ते कॅरिअर निर्धारण, कॅरिअर चयन और कॅरिअर परामर्श को प्रमुखता देनी होगी। यदि शिक्षा की बहु-विषयक व्यवस्था को कॅरिअर निर्धारण और कॅरिअर चयन के साथ अच्छे से जोड़ दिया जाए तो भारत ज्ञान संपन्न समाज बन जाएगा और मानवीय पूंजी की दृष्टि से महाशक्ति बन जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना का एक मूल अंग कौशल विकास पर फोकस करना है। नीति में माना गया है कि आज के तेज़ी से उभरते श्रम बाज़ार में अपने व्यवसायों में सफलता पाने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न योग्यताएं अर्जित करनी होंगी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी मुख्य शिक्षा पद्धति में समाहित करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया है ताकि विद्यार्थी विविध विषयों में कुशलता प्राप्त कर सकें जिससे वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रोज़गार कर सकने की क्षमता हासिल कर लें। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने से विद्यार्थी ऐसी उपयोगी कुशलता प्राप्त कर लेंगे जो उन्हें रोज़गार पाने में सहायक होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 2020 में विद्यार्थियों में ऐसे लचीलेपन का विकास किया जाता है जिसके आधार पर वे अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुरूप कॅरिअर चुन सकते हैं। कला और विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम से अलग गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों के बीच चले आ रहे युगों पुराने भेद को समाप्त करके ही हानिकारक परम्पराओं और कुंठाओं को मिटाया जा सकता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानव विज्ञान और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के विषयों के बारे में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाकर ही शिक्षार्थी ज्ञान की एकता और अखंडता के सहारे उन्नति कर सकते हैं।

समेकित पाठ्यचर्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य आईआईटी, आईआईएस, एनआईटी और विश्वविद्यालयों में लचीले संयोजन वाले और अधिक सुविधाजनक अवधि के पाठ्यक्रम शुरू करना है। इन पाठ्यक्रमों में बहु-विषयक शिक्षण, व्यावसायिक कौशल और शोध-आधारित कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया जाता है। विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाने शुरू कर दिए हैं। भारत में शिक्षा की पारम्परिक पद्धति में किसी विद्यार्थी का साहित्य के साथ कंप्यूटर और कृत्रिम मेधा (एआई) पढ़ना संभव ही नहीं माना जा सकता था। 'हिन्दी साहित्य' के कोर्स के साथ कंप्यूटर स्किल्स और डिजिटल साक्षरता का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हो सकता है खासकर अनुवाद से जुड़े क्षेत्रों में अध्ययन के लिए इनका बहुत महत्व है।

चार्टर्ड एकाउंटेंसी (सीए) जैसे प्रोफेशनल कोर्सों के साथ एलएलबी या एलएलएम (कानूनी पढ़ाई) करने से शिक्षार्थी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से निपुणता प्राप्त कर सकता है। कोई भी कंपनी या फर्म ऐसे प्रत्याशी को अपने यहाँ काम पर रखने में प्राथमिकता देगी क्योंकि इससे उनके संगठन की कार्यदक्षता तो बढ़ेगी ही, साथ में उसका खर्च भी घटेगा। उच्चतम न्यायालय में अभी हाल में सार्वजनिक हित की एक याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की गई जिसमें 5 वर्ष के समेकित (इटेग्रेटेड) एलएलबी की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप 4 वर्ष का लॉ-डिग्री पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया गया था। आने वाले समय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल, विवेचनात्मक सोच और नैतिक जागरूकता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि वे उद्योग की आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के हिसाब से आगे बढ़ते रहें। ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर अध्ययन के साथ रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स की जानकारी होने से कॅरिअर की काफी ज्यादा संभावनाएं खुल जाएंगी। बहु-विषयक पहल देश में स्टार्ट-अप कल्चर को तेज़ी से बढ़ाने में सहायक होगी।

स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कई छोटे कार्यक्रम जोड़े गए हैं ताकि विद्यार्थी अपने मुख्य अकादमिक विषयों में दक्षता हासिल करने के साथ ही नए उभरते क्षेत्रों में बहु-विषयक निपुणता प्राप्त करके वैश्विक रोज़गार बाज़ार की तेज़ी से बदलती मांगों के अनुरूप काम करने में सफल हो सकें। किसी ऑनर्स डिग्री की पढ़ाई के साथ विद्यार्थी राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक और भावनात्मक अध्ययन, समाज में विज्ञान, आयुर्वेद और पोषण, वैदिक गणित, इकोलॉजी एवं साहित्य, नैतिकता एवं संस्कृति, डिजिटल सशक्तीकरण, स्थायी पर्यावरण पर्यटन, योग, व्यापार संचार, चॉकलेट क्रॉफ्ट, वित्तीय नियोजन, राजनीतिक नेतृत्व, भारतीय भाषाओं, ऑर्गेनिक खेती, दस्तावेज़ तैयार करना, पायथन लैंग्वेज़ (प्रोग्रामिंग भाषा), भारतीय पांडुलिपि विज्ञान से लेकर पब्लिक भाषण तक कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 2020 में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक कौशल के विकास पर भी बल दिया गया है। इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी परम्परागत सीमाओं से बाहर जाकर भी संबंधित विषयों को जानने का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनकी जानकारी का आधार बढ़ेगा और कॅरिअर विकल्पों का भी विस्तार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 2020 व्यवसायिक पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतियोगी बना रही है ताकि विद्यार्थी नैतिक आचरण के सर्वोच्च मानक अपनाते हुए कॅरिअर के व्यापक अवसर प्राप्त कर सकें।

अंतरराष्ट्रीयकरण और सहयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीयकरण और सहयोग पर बल दिया गया है। नीति में भारतीय और विदेशी शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है ताकि विद्यार्थी अन्य संस्कृतियों के बारे में जान-समझकर भविष्य में वैश्विक-स्तर पर जुड़े रह सकें। नीति में भारत को उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाने का भी उद्देश्य रखा गया है जिससे विदेशी विद्यार्थी भारत में आकर पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे और हमारे विद्यार्थियों को विदेशी स्कूलों में जाकर पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार विद्यार्थियों के व्यवसायिक विकास को गति मिलेगी और शिक्षा प्रणाली में नए दृष्टिकोण, नवाचार और सूचना पद्धति समाहित की जा सकेगी।

एकाधिक प्रवेश और निकास का विकल्प

राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 2020 में एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों की अनुमति दी गई है जिससे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही अधिक लचीले शिक्षण मार्ग अपनाने में मदद मिलेगी। भारतीय शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने पाठ्यक्रमों में ये सुविधाएं शामिल करने के प्रयासों में लगा है। क्रेडिट (ऋण) आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों को अपनी पसंद और उद्योगों की मांग के अनुसार विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। काम या नौकरी करने के साथ-साथ पढ़ाई करने से शिक्षार्थियों को योग्यता-क्षमता के अनुरूप और रोज़गार-बाज़ार की मांगों के हिसाब से कॅरिअर विकल्प चुनने के अवसर मिलेंगे।

बहु-विषयक पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 2020 के विज़न के अनुसार विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों ने विभिन्न क्षेत्रों में बहु-विषयक पाठ्यक्रमों की व्यापक रेंज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है जिनमें परम्परागत विषयों के साथ कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग, डिजाइन थिंकिंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण अध्ययन, कानूनी पढ़ाई और स्थायित्व जैसे नए उभरते विषय भी शामिल हैं।

कुछ नए शुरू किए क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

पर्यावरण अध्ययन और संधारणीयता : पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास के विषय भी कानून, डेटा प्रबंधन, पारिस्थितिकी, नीति और समाज शास्त्र आदि के साथ समाहित किए जा रहे हैं। कचरा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट भवन निर्माण, सामाजिक उद्यमिता आदि युवाओं के लिए कॅरिअर के विभिन्न विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं।

कला और मानविकी : सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, रचनात्मक लेखन, मीडिया, अन्तरराष्ट्रीय संबंधों, सॉफ्ट स्किल्स और कानून के विषयों के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनमें रोज़गार की बड़ी संभावनाएं हैं।

ज्ञान और प्रौद्योगिकी : कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स के विषय जन प्रशासन, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और सभी परम्परागत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के साथ विशेष बहु-विषयक कार्यक्रमों के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोविज्ञान और संबद्ध विज्ञान: स्वास्थ्य मनोविज्ञान और सामुदायिक स्वास्थ्य के पाठ्यक्रम सामाजिक कार्य, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक स्वास्थ्य, हर्बल पोषण, आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृत चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) और प्रौद्योगिकी के साथ समाहित किए जा सकते हैं।

अर्थशास्त्र और व्यापार : उद्यमशीलता, ई-कॉमर्स और वित्तीय साक्षरता जैसे विषयों में बहु-विषयक पहल देखी जा सकती है और अर्थशास्त्र, व्यापार प्रबंधन, जन नीति, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी को अक्सर संयोजित कर लिया जाता है।

कंप्यूटर साइंस और उद्यमी नेतृत्व : इसमें स्टार्टअप्स और उद्यमशीलता की स्थापना और नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कौशल के साथ कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी को जोड़ लिया जाता है।

समग्र विकास : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विद्यार्थी के समग्र विकास पर ज़ोर दिया जाता है जिसमें उसका शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कल्याण शामिल रहता है। इसका उद्देश्य ऐसे सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुगठित व्यक्ति का विकास करना है जो विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों का पूरे विश्वास और योग्यता के साथ मुकाबला कर सके। विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के समन्वयन और विवेचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्याओं का समाधान कर पाने की क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की समग्र पहल का समर्थन करती है जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान और योग्यता को वास्तविक दुनिया के परिवेशों में व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं।

डिजिटल लर्निंग : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 जीवन और कार्य के सभी क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा अपनाने पर ज़ोर देती है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विद्यार्थी आवश्यक डिजिटल कौशल सीख लेंगे जिससे वे डिजिटल दौर के लिए अच्छे से तैयार हो पाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में समग्र और बहु-विषयक पहल को प्राथमिकता दी जाती है, अनूठी क्षमताएं विकसित करने का लक्ष्य रहता है और शिक्षण की सीमाओं की पहचान बनी रहती है और साथ ही सृजनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता, लचीलापन और जीवनभर सीखते रहने की ललक भी जरूरी है। मुख्य बुनियादी कौशल के मजबूत आधार, लचीला और विविध पाठ्यक्रम और नवाचार-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण के सहारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ऐसे सुविकसित व्यक्ति तैयार करने की असीम क्षमता है जो समाज में सार्थक योगदान कर सकें। इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण तो है परन्तु बहु-विषयक पहल से कॅरिअर विकल्पों की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ❑

(सह-लेखक राजा पंडित भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सलाहकार हैं।)